बिहार विधान परिषद्

187वां सत्र

तारांकित प्रश्न
वर्ग – 2

7 अग्रहायण, 1939 (श.)
मंगलवार, तिथि ----------
28 नवम्बर, 2017 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 22

1.	स्वास्थ्य विभाग	....	....	09
2.	ऊर्जा विभाग	....	....	06
3.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	....	....	03
4.	गन्ना उद्योग विभाग	....	....	02
5.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	....	....	01
6.	विधि विभाग	....	....	01

			कुल योग –	**22**

ट्रामा सेन्टर खोलने पर विचार

***** 1. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पी.एम.सी.एच. के सर्जरी विभाग द्वारा 2016 में किये गये शोध के अनुसार राज्य में सड़क हादसे से घायल होने वालों में 80 प्रतिशत की जान समय पर उपचार और अस्पताल नहीं पहुंचने के कारण हो जाती है और 12 प्रतिशत ऐसे मरीज होते हैं जो अस्पताल तो पहुंच जाते हैं परन्तु देर से उपचार के कारण उनकी मौत हो जाती है;

(ख) क्या यह सही है कि ट्रामा सेन्टर होने पर सड़क हादसे के शिकार मरीजों की जान बच सकती है किन्तु राज्य में सरकारी क्षेत्र में कहीं भी ट्रॉमा सेन्टर नहीं है जिसके कारण मरीजों का उपचार अस्पतालों की इमरजेंसी में करना पड़ता है जहां एक साथ हड्डी, न्यूरो, प्लास्टिक सर्जरी, मेडिसीन और एनेस्थिसिया के डॉक्टर नहीं मिलते हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ऐसी स्थिति में राज्य में अवस्थित राष्ट्रीय राजमार्गों एवं अन्य जगहों पर सरकारी क्षेत्र में ट्रॉमा सेन्टर खोलने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

विद्युत पोल की व्यवस्था

***** 2. **डॉ. संजीव कुमार सिंह** : क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि भागलपुर जिले के रंगरा चौक प्रखंड के मुरली ग्राम पंचायत में अभी तक विद्युत पोल नहीं गाड़े गये हैं लेकिन अधिकांशत: लकड़ी के खम्भों के सहारे तार लगे हुए हैं और विद्युत आपूर्ति भी हो रही है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार इस ग्राम पंचायत में विद्युत पोल कबतक लगाने का विचार रखती है?

शिक्षकों एवं कर्मियों की बहाली

***** 3. **डा. सी.पी. सिन्हा** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार में यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी सहित होम्योपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी राजकीय तिब्बी कॉलेज, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेजों में व्याख्याताओं के कई पद कई वर्षों से रिक्त है;

(ख) क्या यह सही है कि सरकार ने पदों को भरने के लिए अधियाचना, आयोग को भेजी थी जिसे आयोग ने अधियाचना में कई त्रुटियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए इसे विभाग को वापस भेज दिया था;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सूबे में यूनानी होम्योपैथिक, तिब्बती और आयुर्वेदिक चिकित्सा कॉलेजों में शिक्षकों एवं कर्मियों की बहाली कब तक करना चाहती है, नहीं तो क्यों ?

प्रगति शून्य

***** 4. **श्री संजय प्रसाद** : क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि जमुई जिले के ग्राम सनकुरहा में विद्युत सब स्टेशन निर्माण का कार्य शिरडी साईं कम्पनी को दिया गया है, जिसकी प्रगति शून्य है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त कम्पनी बहुत धीमी गति से कार्य कर रही है तथा उसके पास पर्याप्त धनराशि तथा संसाधनों का घोर अभाव है, जिसमें कार्य संपन्न होने में काफी समय लग सकता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इसपर क्या कार्रवाई करेगी ?

जलापूर्ति से वंचित

***** 5. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत मोतिहारी शहर में पाईप लाईन जलापूर्ति योजना वर्ष 2010 में लागू की गई थी, जिसके अन्तर्गत 9.67 करोड़ पाईप लाईन पुनर्गठन जलापूर्ति योजना पर खर्च करना था, जिससे 3 वाटर टावर का निर्माण कराना था जिसमें पी.एच.ई.डी. कैम्पस में 1.10 लाख गैलन (2) छोटा बरियारपुर में 1.20 लाख गैलन व (3) अगरवा में 1.75 लाख गैलन क्षमता के वाटर टावर शामिल है;

(ख) क्या यह सही है कि तीसरा वाटर टावर अगरवा मोतिहारी का निर्माण नहीं कराया गया है तथा जो 2 टावर बने हैं उनसे जलापूर्ति नहीं होती है जिसका कारण रैंडओवर है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो बने हुए 2 वाटर टावरों से जलापूर्ति कब होगी 1 वाटर टावर अब क्यों हटा तथा इस योजना में कितनी राशि खर्च की गई, अवशेष राशि का क्या हुआ? जिन पदाधिकारियों के चलते मोतिहारी शहरवासी जलापूर्ति से वंचित हुए उनपर सरकार कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो कयों ?

मीटर स्थापित करने पर विचार

***** 6. **श्री रामचन्द्र भारती** : क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड के छपरा पूर्वी डिविजन के मढ़ौरा सब डिविजन में उपभोक्ताओं को मीटर लगाने एवं विद्युत विपत्र उपलब्ध कराने में घोर अनियमितता बरती जा रही है;

(ख) क्या यह सही है कि स्थानीय पदाधिकारियों के मनमाने रवैये के कारण मढ़ौरा सब डिविजन में नया कनेक्शन लेने पर या मीटर खराब होने की स्थिति में दो तीन वर्ष बीतने के बावजूद भी नया मीटर स्थापित नहीं किया जाता है;

(ग) क्या यह सही है कि विभागीय पदाधिकारियों की इस लापरवाही का खामियाजा वहां के उपभोक्ताओं को दुगुना विपत्र चुका कर भुगतान करना पड़ रहा है जो कि अनुचित है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस मामले में दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा प्रभावित उपभोक्ताओं के यहां शीघ्र मीटर स्थापित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

वेतन निर्धारण पर विचार

***** 7. **डा. उपेन्द्र प्रसाद** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि आई.जी.आई.एम.एस., पटना बिहार सरकार का स्वसंचालित संस्थान है जो ए.आई.आई.एम.एस., नई दिल्ली के नियमानुसार शत-प्रतिशत संचालित है;

(ख) क्या यह सही है कि आई.जी.आई.एम.एस., पटना में कार्यरत लैब कर्मी का ए.आई.आई.एम.एस., नई दिल्ली के नियमानुसार नियुक्ति, प्रोन्नति, वेतनादि भुगतान एवं कैडर रिविजन किया जाता है;

(ग) क्या यह सही है कि ए.आई.आई.एम.एस., नई दिल्ली अपने लैब कर्मी को पत्रांक-एफ. 9-34/2008-ई.एस.टी.टी. (आर.सी.टी.) पी.एफ. दिनांक 2 अप्रील, 2016 द्वारा कैडर और पेव स्ट्रक्चर का रिविजन किया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार ए.आई.आई.एम.एस. की तर्ज पर आई.जी.आई.एम.एस. के लैब कर्मियों का कैडर एवं वेतन निर्धारण करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

अद्यतन भुगतान

***** 8. **श्री दिलीप राय** : क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि उत्तर बिहार के रीगा चीनी मिल प्रबंधन के पास अभी तक विगत पेराई सत्र 2016-17 के गन्ना मूल्य का करीब-करीब 22 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त चीनी मिल के प्रबंधन द्वारा पिछले चार-पांच सत्रों से किसानों को तबाह किया जा रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त चीनी मिल के चीनी, छोआ तथा स्प्रिट की बिक्री कर किसानों के खाते में पैसा जमा नहीं किया जाता है और किसानों का काफी पैसा लगातार बकाया रख दिया जाता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किसानों को सूद सहित अद्यतन भुगतान करना चाहती है और चीनी मिल प्रबंधन द्वारा बेचे गए चीनी, छोआ तथा स्प्रिट की बिक्री 'रिसिवर' के माध्यम से कराकर किसानों के खाता में सीधा पैसा जमा करवाना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

अद्यतन जानकारी

***** 9. **श्री नीरज कुमार** : क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 2500 डेडीकेटेड फीडर का निर्माण किसानों की खेती करने के लिए 11 के.वी.ए. का बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या यह सही है कि है इन डेडीकेटेड फीडरों को टेंडर के बाद 2 साल में पूरा करने की हिदायत दी गई है, यदि तय समय सीमा में निर्माण नहीं किया गया तो राज्य सरकार को 25 प्रतिशत की जगह 40 प्रतिशत राशि व्यय करनी होगी;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इन डेडीकेटेड फीडरों के निर्माण के बारे में अद्यतन जानकारी देना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

बकाया राशि का भुगतान

***** 10. **श्री राजेश राम** : क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि तिरूपति सुगर्स लिमिटेड, बगहा के जिम्मे बगहा के गन्ना काश्तकारों का वित्तीय वर्ष 1998 से 2003 तक का राशि बकाया है;

(ख) क्या यह सही है कि एच.एम.पी., सुगर मिल्स, बगहा से सुगर मिल, बगहा को क्रय करते समय किसानों एवं मजदूरों की जो बकाया राशि एच.एम.पी. सुगर मिल्स के उपर थी उक्त राशि तिरूपति सुगर्स मिल, बगहा ने अपने उपर ले लिया था जो राशि आज तक बकाया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो किसानों के बकाया राशि का भुगतान सरकार कबतक कराना चाहती है ?

इन्सूलेटेड तार की व्यवस्था

***** 11. **श्री सूरजनंदन प्रसाद** : क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत अनीसाबाद के मित्रमंडल कॉलोनी के डी सेक्टर स्थित बिहार होटल से लेकर जायसवाल के घर के समीप ट्रांसफार्मर तक बिजली का खुला तार काफी जर्जर है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त पोल पर खुला तार का जाल बिछा हुआ है जिससे कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है;

(ग) क्या यह सही है कि विद्युत पोल से उपभोक्ताओं के मीटर तक विभाग द्वारा इन्सूलेटेड तार नहीं रहने से कई जगहों पर बिजली की चोरी धड़ल्ले से की जाती है जिससे सरकारी राजस्व की क्षति हो रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार होटल से लेकर जायसवाल के घर तक केबुल तार के साथ-साथ विद्युत उपभोक्ताओं के घर के मीटर तक इन्सूलेटेड तार लगाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

भवन बनाने पर विचार

***** 12. **श्री राधाचरण साह** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि है बक्सर जिलान्तर्गत चक्की प्रखंड के ग्राम पंचायत अरक में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन बिल्कुल जर्जर स्थिति में है;

(ख) क्या यह सही है कि है प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन जर्जर स्थिति में होने के कारण बड़ी दुर्घटना हो सकती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार कबतक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन बनाने का विचार रखती है ?

वार्ड खोलने पर विचार

***** 13. **श्री संजीव श्याम सिंह** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, गया राज्य का एक महत्वपूर्ण अस्पताल है एवं यहां गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, झारखंड के चतरा आदि जिलों के लोग भी ईलाज कराने हेतु आते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि यहां न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, अंकोलॉजी इत्यादि का सुपर स्पेशियलिटी वार्ड नहीं है;

(ग) क्या यह सही है कि इन विभागों का सुपर स्पेशयलिटी वार्ड नहीं होने से गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों का इलाज नहीं हो पाता है और मरीजों को पी.एम.सी.एच., पटना रेफर करना पड़ता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विभागों का सुपर स्पेशलिटी वार्ड खोलने का विचार रखती है ?

विद्युतीकरण कबतक

***** 14. **डा. रामवचन राय** : क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि जहानाबाद जिले के मखदुमपुर प्रखंड के ग्राम सेवती गोलबिगहा, काजीचक और भगवान खंधा आदि गांवों में विद्युत की सप्लाई जारी है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त प्रखंड के ग्राम ओड़बिगहा टोला पुन्हदा, लालमनचक और पोखर पर (सेवती) आदि गांवों में विद्युत पोल गाड़ा गया, बावजूद इसके इन गांवों में न तो तार टांगा गया और न ही ट्रांसफार्मर बैठाया गया, जिसके कारण वहां वर्षों से बिजली उपलब्ध नहीं है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त गांवों में विद्युतीकरण नहीं होने के कारण वहां के बच्चों के पठन-पाठन एवं कृषि कार्य प्रभावित है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खंड 'ख' में वर्णित उक्त गांवों का विद्युतीकरण अविलम्ब कराना चाहती हे, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

भवन का निर्माण

***** 15. **मो. गुलाम रसूल** : क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अंजुमन ईस्लामिया हॉल, पटना के स्थान पर एक नई बहुमंजिली एवं बहुद्देशीय भवन बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था एवं इसके लिए राशि भी आवंटित की गई थी;

(ख) क्या यह सही है कि प्रस्ताव पारित होने एवं राशि आवंटित किए जाने के बावजूद भी अबतक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अंजुमन ईस्लामिया हॉल के नए भवन के निर्माण की इच्छा रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

न्यायालय चालू करने पर विचार

***** 16. **श्री रामलषण राम 'रमण'** : क्या मंत्री, विधि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर अनुमंडल मुख्यालय के व्यवहार न्यायालय में दो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पदों की स्वीकृति बिहार सरकार के मंत्री परिषद द्वारा वर्ष 2013 ई. में दी गई;

(ख) क्या यह सही है कि भवन का अभाव दर्शा कर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय का कार्यारंभ नहीं हो पा रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि अनुमंडल पदाधिकारी का कार्यालय नये भवन में स्थानान्तरित हो जाने के कारण पुराना भवन पुरी तरह खाली है जहां अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय आसानी से चलाया जा सकता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक अनुमंडल पदाधिकारी के खाली भवनों में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय चालू करना चाहती है ?

विशेष दस्ता का गठन

***** 17. **डा. दिलीप कुमार जायसवाल** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि तम्बाकू नियंत्रण के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति का चालान एवं स्पॉटफाईन बुकलेट उपलब्ध कराया गया है, परन्तु इससे संबंधित कोई भी निरोधात्मक कार्रवाई त्वरित गति से नहीं हो रही है;

(ख) क्या यह सही है कि संपूर्ण बिहार एवं विशेषकर पूर्णियां, अररिया एवं किशनगंज जिले में धड़ल्ले से तम्बाकू छुट्टा सिगरेट एवं गुटका बेचा जा रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि तम्बाकू नियंत्रण पदाधिकारियों की अकर्मण्यता से पूरे बिहार राज्य में कार्यक्रम असफल साबित हो रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार तम्बाकू नियंत्रण के लिए प्रत्येक जिला में छापेमारी के लिए विशेष दस्ता का गठन करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

पानी टंकी चालू करने पर विचार

***** 18. **श्री हरिनारायण चौधरी** : क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि समस्तीपुर जिला अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में पानी की टंकी की सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी है;

(ख) क्या यह सही है कि जितने भी पानी की टंकी उपलब्ध हैं प्राय: खराब हालत में है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार यह बतलाए कि उक्त जिले में कितने पानी टंकी उपलब्ध हैं, उसमें कितने चालू स्थिति में है एवं कितने बंद पड़े है। बंद पड़े पानी टंकी को सरकार कबतक चालू करना चाहती है ?

स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण

***** 19. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि गया जिलान्तर्गत नगर प्रखंड के कंडी पंचायत में आज तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण नहीं किया गया है, जिससे प्रसव पीड़ा से पीडित मरीजों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या यह सही है कि विभाग उक्त पंचायत में जमीन नहीं रहने का हवाला देकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण में रूचि नहीं ले रही है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त पंचायत के मौजा बीथों, थाना नं.-193, खाता नं.-484, खेसरा नं.-1618, 2915, 2917 रकबा करीब 89 डिसमिल जमीन बिहार सरकार को उपलब्ध है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खंड 'क' में वर्णित पंचायत में कबतक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराना चाहती है ?

आवश्यक कार्रवाई

***** 20. **श्री राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवार के रोगियों का प्राइवेट हॉस्पीटल द्वारा इलाज किया गया;

(ख) क्या यह सही है कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस द्वारा बी.पी.एल. परिवार के रोगियों पर हुआ खर्च प्राइवेट नर्सिंग होम को अबतक नहीं दिया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्राइवेट नर्सिंग होम को यथाशीघ्र भुगतान हेतु आवश्यक कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

शुद्ध जल की व्यवस्था

***** 21. **श्री रणविजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि भोजपुर जिला के बढ़हरा प्रखंड आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्र है यहां के लोग शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं रहने के कारण तरह-तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं;

(ख) क्या यह सही है कि सरकार ने हर घर शुद्ध जल पहुंचाने के लिए संकल्प लिया है, परन्तु विभागीय स्तर से उक्त प्रखंड में शुद्ध जल नहीं पहुंचाया जा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड में शुद्ध जल पहुंचाने के लिए व्यवस्था कर रही है, यदि नहीं तो क्यों ?

भवन का निर्माण

***** 22. **श्री सच्चिदानन्द राय**: क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि छपरा जिलान्तर्गत रेफरल अस्पताल बनियापुर का मुख्य भवन जर्जर हो गया है, जिसमें मरीजों का ईलाज करना खतरनाक है;

(ख) क्या यह सही है कि पुरानी जर्जर भवन मरम्मत के योग्य नहीं है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंडहर में तब्दील होते भवन के स्थान पर नया भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पटना
दिनांक 28 नवम्बर, 2017 ई.

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्